IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों का उद्‌भव

शोधार्थी :–रेणु चौहान

भूगोल विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

पर्यवेक्षक :– प्रो. डॉं ओम प्रकाश देवासी

आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय चौपासनी, जोधपुर।

शोध सारांश – जोधपुर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। विगत कुछ दशकों में इस शहर ने तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। इन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के साथ ही मलिन बस्तियों (सनउे) का भी तेजी से विकास हुआ है, जो शहरी नियोजन की चुनौतियों और विसंगतियों को दर्शाते हैं। इस शोध में जोधपुर शहर की मलिन बस्तियों के उद्‌भव के प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया है। सर्वप्रथम, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला पलायन एक मुख्य कारक पाया गया। बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की आशा में लोग जोधपुर की ओर आकर्षित हुए, किंतु शहर की सीमित आवासीय सुविधाओं और उच्च भूमि मूल्यों के कारण ये लोग अनाधिकृत बस्तियों में बसने को मजबूर हो गए। द्वितीय, औद्योगिक विकास और निर्माण कार्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को भी पर्याप्त व सुरक्षित आवास न मिल पाने के कारण वे अस्थायी झोपड़ियों में निवास करने लगे, जो समय के साथ स्थायी मलिन बस्तियों में बदल गईं। तृतीय, शहरी नियोजन में सरकार की लचर नीति, अवैध निर्माण पर नियंत्रण की कमी, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित पहुँच भी मलिन बस्तियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी रहे। शोध में यह भी सामने आया कि जोधपुर की कई मलिन बस्तियाँ नगर के पुराने भागों तथा रेलवेलाइन, जलाशयों, पहाड़ियों और सार्वजनिक जमीनों के निकट विकसित हुई हैं। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ जल, शौचालय, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी देखी गई।

जोधपुर में मलिन बस्तियों का उद्‌भव सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारणों का सम्मिलित परिणाम है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं ताकि एक समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

संकेताक्षर :– मलिन बस्ती की परिभाषा, जोधपुर शहर का संक्षिप्त परिचय एवं शहरीकरण की दर, जोधपुर का शहरी विकास और जनसंख्या वृद्धि, मलिन बस्तियों का उद्‌भव, जोधपुर की प्रमुख मलिन बस्तिया, भौगोलिक और सामाजिक विश्लेषण, जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के लिए सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ, जोधपुर शहर में मलिन बस्तियाँ – चुनौतियाँ और समाधान के सुझाव ।

प्रस्तावना – भारत में शहरीकरण की तीव्र गति ने एक ओर जहाँ विकास की नई संभावनाएँ प्रस्तुत की हैं, वहीं दूसरी ओर इससे कई सामाजिक व भौगोलिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख और जटिल समस्या मलिन बस्तियों (सनउे) की वृद्धि है। मलिन बस्तियाँ शहरी गरीबी, असमानता, अव्यवस्थित आवास व्यवस्था और सामाजिक–आर्थिक असंतुलन की स्पष्ट प्रतीक हैं। जोधपुर शहर, जो कि राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र है, इन समस्याओं से अछूता नहीं

रहा है। जोधपुर का तेजी से होता नगरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन ने शहर पर आवास और आधारभूत संरचना की भारी मांग डाली है। किन्तु नगरीय विकास की योजनाएँ और संसाधन इस मांग के अनुरूप नहीं रहे, जिसके परिणामस्वरूप शहर में कई अनधिकृत और अव्यवस्थित बस्तियाँ विकसित हुई हैं। ये बस्तियाँ सामान्यतः जल स्रोतों, रेलवे लाइनों, नगर सीमा के बाहरी हिस्सों, और सार्वजनिक भूमि के निकट विकसित होती हैं, जहाँ शासन और प्रशासन की सीधी निगरानी न्यूनतम होती है। इस शोध का उद्देश्य जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के उद्भव के कारणों, उनके विकास के चरणों, और वहाँ निवास करने वाले लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही, शहरी नियोजन की खामियाँ, और नीति निर्धारण की असफलताएँ इस समस्या को जन्म देती हैं।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और स्थायी रोजगार की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है, बल्कि सम्पूर्ण शहरी तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस शोध के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि जोधपुर की मलिन बस्तियाँ केवल एक भौगोलिक या भौतिक समस्या नहीं हैं, बल्कि यह एक सामाजिक–आर्थिक संकट का परिणाम हैं। इस संकट के समाधान हेतु स्थानीय निकायों, शहरी नियोजन एजेंसियों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि एक समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी भविष्य का निर्माण किया जा सके।

मलिन बस्ती की परिभाषा

मलिन बस्ती ¨(सनउ) ऐसे आवासीय क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ रहने की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पानी, शौचालय, सड़क, कचरा निपटान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का अभाव होता है। भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, मलिन बस्तियाँ वे क्षेत्र हैं जहाँ मकान जर्जर अवस्था में हैं, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, स्वच्छता की स्थिति अत्यंत खराब है, तथा रहने की स्थिति अस्वास्थ्यकर एवं असुरक्षित है।

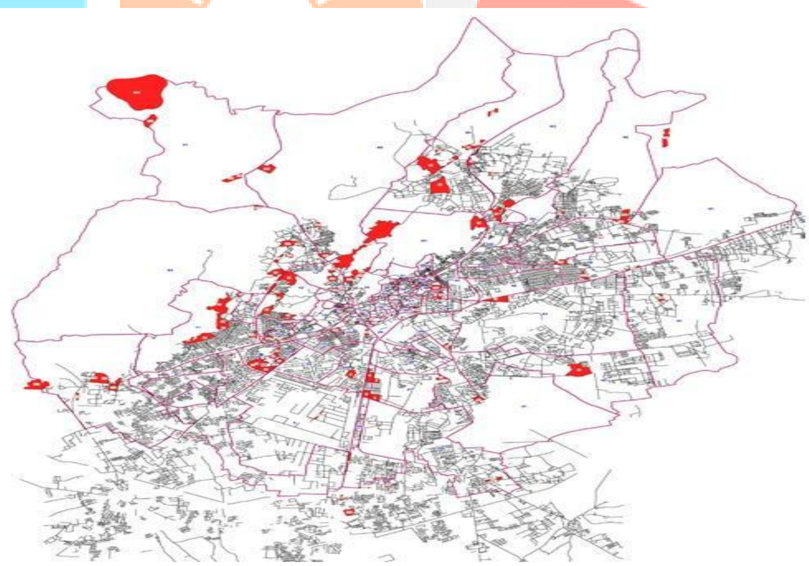

भारत और राजस्थान में मलिन बस्तियों की स्थिति – भारत में तीव्र शहरीकरण, गरीबी और पलायन के कारण मलिन बस्तियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, देश के लगभग 65 मिलियन लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। महानगरों से लेकर मध्यम और छोटे शहरों तक मलिन बस्तियाँ सामान्य दृश्य बन गई हैं। राजस्थान जैसे राज्य, जहाँ शहरीकरण हाल के वर्षों में तीव्र हुआ है, वहाँ भी मलिन बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहरों में कई दर्जन मलिन बस्तियाँ मौजूद हैं, जिनमें रहने वाले अधिकांश लोग निम्न आय वर्ग से आते हैं।

जोधपुर शहर का संक्षिप्त परिचय एवं शहरीकरण की दर – जोधपुर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा है। यह शहर अपने किलों, महलों और मरुभूमि के सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। हाल के वर्षों में जोधपुर में औद्योगिकीकरण, व्यापार, पर्यटन और सेवाक्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ शहरीकरण की गति तेज हुई है। 2001 से 2011 के बीच शहर की जनसंख्या में लगभग 27 प्रति"ात की वृद्धि दर्ज की गई, और शहरी क्षेत्र का विस्तार नगर सीमा से बाहर की ओर हुआ। इससे आवास की मांग में वृद्धि हुई, जिसे पूरा करने में नगर नियोजन असमर्थ रहा, और परिणामस्वरूप अनेक मलिन बस्तियाँ अस्तित्व में आईं।

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के उद्भव, विस्तार और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना है। शोध के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि किन कारणों से मलिन बस्तियाँ बनती हैं, वहाँ निवास कर रहे

लोगों की जीवनशैली कैसी है, तथा सरकार और नगर निगम की योजनाएँ कितनी प्रभावशाली हैं। इस अध्ययन का महत्व इस दृ ष्टिकोण से है कि यह नीति निर्माताओं, नगर नियोजन अधिकारियों और सामाजिक संगठनों को मलिन बस्तियों की समस्या की गहराई से समझ प्रदान कर सकेगा, जिससे एक समावेशी, स्वच्छ और टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकें।

जोधपुर का शहरी विकास और जनसंख्या वृद्धि

जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ई. में राव जोधा द्वारा की गई थी, और यह मारवाड़ रियासत की राजधानी रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह शहर व्यापार, कला, संस्कृति और स्थापत्य का केंद्र रहा है। प्राचीन समय में जोधपुर का विकास मेहरानगढ़ किले के चारों ओर हुआ और शहर दीवारों से घिरा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से 1950 के दशक के बाद, जोधपुर में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। इसके पीछे मुख्य कारण थे रेलवे और सड़क परिवहन का विकास, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना।

जनसंख्या वृद्धि के आँकड़े

जोधपुर में जनसंख्या वृद्धि की गति पिछले कुछ दशकों में काफी तेज रही है।

- 1951 में जोधपुर की जनसंख्या लगभग 2.7 लाख थी।
- 1981 में यह बढ़कर लगभग 5.7 लाख हो गई।
- 2001 में यह संख्या 8.6 लाख तक पहुँच गई।
- 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर शहर की जनसंख्या लगभग 10 लाख के पार हो गई।
- 2023–24 के अनुमानित आँकड़ों के अनुसार, यह संख्या 13–14 लाख तक पहुँच चुकी है।

इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने शहर की आधारभूत संरचना, आवासीय व्यवस्था, परिवहन और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है।

ग्रामीण–शहरी प्रवासन की भूमिका

जोधपुर का विकास न केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, बल्कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों के कारण भी हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण लोग बेहतर जीवन की तलाश में जोधपुर जैसे शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। पलायन करने वाले अधिकांश लोग निम्न आय वर्ग से होते हैं और निर्माण, घरेलू कार्य, रिक्शा चलाने, ठेला व्यवसाय जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। यह प्रवासन शहर में श्रम शक्ति की आपूर्ति तो करता है, लेकिन साथ ही मलिन बस्तियों के विस्तार को भी बढ़ावा देता है।

अनियोजित शहरीकरण की समस्या – जोधपुर का शहरी विकास अक्सर अनियोजित रहा है। नगर योजना विभाग और प्रशासनिक निकायों द्वारा समय पर प्रभावी और समावेशी योजनाएँ न बनाए जाने के कारण शहर के विभिन्न भागों में अनधिकृत निर्माण और अवैध बस्तियाँ उभरती गईं। मूलभूत सुविधाओं की असमान उपलब्धता, ट्रैफिक की समस्याएँ, कचरा निपटान की असफलता, और हरित क्षेत्र में कमी दृ ये सभी अनियोजित शहरीकरण के दुष्परिणाम हैं।

जोधपुर का शहरी विकास ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन और अनियोजित विकास ने इसे कई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। यदि इस विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाना है, तो बेहतर शहरी नियोजन, प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास नीतियाँ, और मलिन बस्तियों के उन्नयन की योजनाएँ अत्यंत आवश्यक हैं।

मलिन बस्तियों का उद्भव

भारत जैसे विकासशील देशों में मलिन बस्तियाँ ;ैसनउे) शहरी विकास की एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुकी हैं। मलिन बस्तियाँ केवल अव्यवस्थित और अस्वस्थ आवासीय क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक–आर्थिक असमानता, सरकारी नीतिगत विफलताओं और शहरी नियोजन की कमियों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। मलिन बस्तियों के उद्भव के कई कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक असमानता, गरीबी, प्रवासन, आवास की सहजता, सरकारी योजनाओं की अक्षमता, और भूमि पर अवैध कब्जा प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इस लेख में इन सभी कारणों का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. **आर्थिक असमानता और गरीबी –** भारत में आर्थिक असमानता की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में एक ओर उच्च आय वर्ग है जो सुविधाजनक जीवन व्यतीत करता है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। गरीबों के पास न पर्याप्त धन होता है और न ही सामाजिक सुरक्षा, जिससे वे बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। परंतु शहरी क्षेत्रों में उनके लिए न तो उचित आवास उपलब्ध होता है और न ही भूमि सुलभ होती है। इस वर्ग के लोग किराये पर रहने में असमर्थ होते हैं और अंततः सस्ती, अव्यवस्थित तथा अनधिकृत बस्तियों में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। आर्थिक असमानता उन्हें शहरी समाज की मुख्यधारा से बाहर कर देती है, और वे मलिन बस्तियों में अपना जीवन यापन करने लगते हैं।

2. रोजगार की तलाश में प्रवास – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जलवायु असुरक्षा, बेरोजगारी और सीमित संसाधनों के कारण लोग शहरी केंद्रों की ओर प्रवास करते हैं। शहरों में औद्योगिक इकाइयाँ, निर्माण कार्य, घरेलू सेवाएँ, एवं अनौपचारिक क्षेत्र उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। हालाँकि यह रोजगार अस्थायी, असंगठित और कम आय वाला होता है, जिससे प्रवासी मजदूर किसी व्यवस्थित कॉलोनी में घर नहीं ले सकते। ऐसे में वे शहरी सीमा के निकट, सरकारी या निजी भूमि पर अस्थायी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगते हैं। समय के साथ जब इन क्षेत्रों में अधिक प्रवासी बसते हैं, तो वे मलिन बस्तियों का रूप ले लेते हैं।

3. सस्ती और सहज बसावट की आवश्यकता – शहरी गरीबों के लिए सस्ती और सहज बसावट की आवश्यकता प्राथमिक होती है। बड़े शहरों में जमीन और मकान के दाम इतने अधिक होते हैं कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वहां रहना लगभग असंभव होता है। परिणामस्वरूप, वे ऐसे स्थानों पर बस जाते हैं जहाँ जमीन की कीमतें कम होती हैं या सार्वजनिक भूमि आसानी से उपलब्ध होती है। रेलवे लाइन के किनारे, नदी तटों, नालों, जलाशयों, पहाड़ियों या कूड़ा डंपिंग यार्ड के पास ऐसी बस्तियाँ बनती हैं, जहाँ सामान्य नागरिक रहना नहीं चाहता। इन स्थानों पर न तो सरकारी निगरानी होती है और न ही कोई प्रशासनिक दबाव, जिससे लोग स्वतंत्र रूप से बस जाते हैं। धीरे–धीरे ये क्षेत्र बस्तियों में बदल जाते हैं जो सुविधाओं के अभाव के बावजूद उन्हें न्यूनतम आश्रय प्रदान करते हैं।

4. सरकारी आवासीय योजनाओं की कमी – भारत में शहरी गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई गई हैं जैसे दृ प्रधानमंत्री आवास योजना (च्ड।ल), राजीव आवास योजना, और राज्य सरकारों की स्थानीय योजनाएँ। परंतु इन योजनाओं की पहुँच सीमित है और इनका क्रियान्वयन कई बार भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भूमि विवाद और तकनीकी जटिलताओं के कारण प्रभावित होता है। अक्सर इन योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता। साथ ही, कुछ योजनाओं में पात्रता की कठोर शर्तें होती हैं, जैसे पहचान पत्र, भूमि स्वामित्व का प्रमाण, आदि, जो शहरी गरीबों के पास नहीं होते। इसके अतिरिक्त, आवास योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले घर शहर की बाहरी सीमा पर होते हैं जहाँ रोजगार, परिवहन और शिक्षा जैसी सुविधाओं की भारी कमी होती है, जिससे लोग उन घरों को छोड़कर पुनः मलिन बस्तियों में लौट आते हैं।

5. भूमि पर अवैध कब्जा और नियमितीकरण की नीतियाँ – शहरी क्षेत्रों में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा एक आम समस्या है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी खाली भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करता है और वहां झोंपड़ी बनाकर बसता है, तो धीरे–धीरे वह बस्ती आकार लेने लगती है। राजनीतिक लाभ या मानवीय दृष्टिकोण से अक्सर सरकारें इन बस्तियों को तोड़ने के बजाय उन्हें षनियमितष करने की नीति अपनाती हैं, अर्थात उन्हें वैध घोषित कर दिया जाता है और कुछ बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान

की जाती हैं। इस प्रवृत्ति से अन्य लोग भी ऐसी भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है।

यह प्रक्रिया चुनावी राजनीति से भी जुड़ी होती है, जहाँ बस्तीवासियों को संभावित मतदाता के रूप में देखा जाता है और उनके पुनर्वास या बेदखली के विषय में निर्णय जनहित से अधिक राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

मलिन बस्तियों का उद्भव कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संरचनाओं की कमजोरी से उत्पन्न होती है। गरीबी, असमानता, प्रवासन, आवास की अनुपलब्धता और सरकारी योजनाओं की विफलता सभी मिलकर इस समस्या को जन्म देते हैं।

शहरी नियोजन में यदि मलिन बस्तियों की समस्या को प्राथमिकता दी जाए, तो इसका समाधान संभव है। इसके लिए आवश्यक है –

समावेशी और सुलभ आवासीय योजनाएँ, प्रवासी श्रमिकों की पहचान और उन्हें कानूनी अधिकारों का संरक्षण, भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी प्रशासन, शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में किफायती आवास का निर्माण, और नवाचार आधारित समाधान जैसे सामुदायिक आवास, किराये की व्यवस्था, सहकारी हाउसिंग, आदि।

जब तक इन मूलभूत कारणों को संबोधित नहीं किया जाएगा, तब तक मलिन बस्तियों का विस्तार शहरी विकास की एक अनचाही सच्चाई बना रहेगा। इसलिए मलिन बस्तियों को हटाने की बजाय, उन्हें सुधारने, पुनर्वासित करने और उनमें रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में प्रयास करना अधिक मानवीय और टिकाऊ विकल्प है।

जोधपुर की प्रमुख मलिन बस्तिया–

जोधपुर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ–साथ तेजी से विकसित होता हुआ शहरी केंद्र है। हालांकि, इस शहरी विकास के साथ–साथ शहर में मलिन बस्तियों की संख्या और क्षेत्रफल में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीचे जोधपुर की कुछ प्रमुख मलिन बस्तियों, उनकी स्थिति, जनसंख्या, जीवन स्तर और मूलभूत सुविधाओं की चर्चा की गई है –

प्रमुख मलिन बस्तियाँ एवं उनके स्थान

1. सूरसागर क्षेत्र की बस्तियाँ – सूरसागर जोधपुर के पुराने शहर का हिस्सा है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से घनी बस्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई अनधिकृत बस्तियाँ विकसित हो चुकी हैं। स्थिति पुराने शहर के भीतर, मेहरानगढ़ किले के समीप। जनसंख्या लगभग 10,000 से अधिक लोग यहाँ मलिन परिस्थितियों में निवास करते हैं। विशेषता क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण गलियों वाला है, जहाँ साफ–सफाई और जल निकासी की गंभीर समस्या है।

2. जालोरी गेट क्षेत्र की बस्तियाँ – जालोरी गेट जोधपुर के वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है, परंतु इसके आस–पास कई अव्यवस्थित बस्तियाँ पनप चुकी हैं। स्थिति शहर के मध्य भाग में, रेलवे स्टेशन से समीप। जनसंख्या अनुमानतः 5,000 – 6,000 लोग। विशेषता रोजगार के लिए आसान पहुँच होने के कारण यह क्षेत्र प्रवासियों के लिए आकर्षक है। परंतु यहाँ शौचालय, स्वच्छ जल और विद्युत आपूर्ति की भारी कमी है।

3. चोपासनी हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित बस्तियाँ – यह क्षेत्र जोधपुर के बाहरी विस्तार में आता है, जहाँ ग्रामीण प्रवासियों ने स्थायी रूप से झुग्गियाँ बसा रखी हैं। स्थिति चोपासनी क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर। जनसंख्या लगभग 8,000 – 10,000 निवासी। विशेषता सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बस्तियाँ विकसित हुई हैं, जहाँ मूलभूत सेवाएँ जैसे सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालयों की पहुँच सीमित है।

4. प्रतापनगर व न्यू पाली रोड क्षेत्र की बस्तियाँ – यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन यहां भी कुछ मलिन बस्तियाँ पनपी हैं। जनसंख्या लगभग 4,000 – 5,000 लोग। विशेषता इस क्षेत्र में शहरी गरीब निर्माण कार्यों में लगे होते हैं और काम के पास ही अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं।

मूलभूत सुविधाओं की स्थिति

जोधपुर की अधिकांश मलिन बस्तियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है–

जल आपूर्ति– अधिकतर बस्तियाँ नगर निगम की जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़ी नहीं हैं। जल के लिए टैंकरों पर निर्भरता होती है।

स्वच्छता एवं शौचालय – सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी है। कुछ क्षेत्रों में खुले में शौच अब भी प्रचलित है।

नाली एवं कचरा निस्तारण– नालियाँ खुली रहती हैं, जल जमाव की समस्या आम है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं।

बिजली– अस्थायी या अवैध कनेक्शन आम हैं, जिससे आग लगने और दुर्घटनाओं की आशंका रहती है।

स्वास्थ्य व शिक्षा – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं विद्यालयों की दूरी अधिक है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होती हैं।

भौगोलिक और सामाजिक विश्लेषण

भौगोलिक दृष्टि से, जोधपुर की मलिन बस्तियाँ या तो पुराने शहर के भीतर अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं (जैसे सूरसागर, जालोरी गेट), या नगर सीमा के बाहर बसे नए विकास क्षेत्रों के पास (जैसे चोपासनी, प्रतापनगर)।

- पुराने क्षेत्रों में बस्तियाँ सीमित भूमि में संकरी गलियों के रूप में विकसित हुई हैं।
- बाहरी क्षेत्रों में अधिकतर बस्तियाँ अस्थायी प्रकृति की हैं, जिनका विकास बिना किसी नियोजन के हुआ है।
- सामाजिक दृष्टि से, इन बस्तियों में निवास करने वाले लोग मुख्यतः निम्न आय वर्ग के प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, ठेले वाले, रिक्शा चालक, सफाईकर्मी आदि होते हैं।
- जातिगत संरचना भी इन बस्तियों में एक भूमिका निभाती है, जहाँ अक्सर वंचित वर्गों के लोग अधिक संख्या में रहते हैं।
- महिला और बालकों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक होती है, क्योंकि उन्हें न तो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती हैं, और न ही शिक्षा और पोषण।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच सीमित होती है, और पहचान दस्तावेजों के अभाव में अनेक परिवार सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं।

जोधपुर की मलिन बस्तियाँ शहरी विकास की छाया में उपजी वे वास्तविकताएँ हैं जो शहरी नियोजन, प्रशासनिक अक्षमता, और सामाजिक विषमता की ओर इशारा करती हैं। इन बस्तियों के उन्नयन और विकास हेतु आवश्यक है–

- किफायती आवास योजना का विस्तार,
- सार्वजनिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण,
- स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की पहुँच बढ़ाना,
- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

जब तक मलिन बस्तियों को शहरी विकास के परिधि से निकालकर केंद्र में नहीं लाया जाएगा, तब तक एक समावेशी, सुरक्षित और सतत् शहर की कल्पना अधूरी ही रहेगी।

जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

जोधपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहरी केंद्र में मलिन बस्तियाँ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी हैं। ये बस्तियाँ न केवल अव्यवस्थित जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि इनके कारण शहर में असमानता, अस्वास्थ्यकर वातावरण और सामाजिक तनाव भी बढ़ता है।

1. शिक्षा की स्थिति – मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा अत्यंत प्रभावित होती है। विद्यालयों की दूरी और परिवहन की सुविधा न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अधिकांश परिवारों की प्राथमिकता जीविकोपार्जन होती है, जिसके कारण बच्चे भी मजदूरी या घरेलू काम में लग जाते हैं। विद्यालयों में नामांकन तो होता है, लेकिन उपस्थिति कम और ड्रॉपआउट दर अधिक होती है। लड़कियों की शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि वे घरेलू कार्यों में अधिक समय लगाती हैं।

2. स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति – मलिन बस्तियों में स्वच्छता और पर्याप्त पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद खराब स्थिति में होती हैं। टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल और प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ नहीं के बराबर होती हैं। जलजमाव, कचरे का ढेर और गंदे नालों के कारण मच्छरजनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आम हैं। निजी अस्पतालों के खर्च वहन करने में असमर्थता और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच एक बड़ी चुनौती है।

3. रोजगार की स्थिति – मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जैसे दृ निर्माण मजदूरी, घरेलू कार्य, ठेला व्यवसाय, कबाड़ी का काम आदि। इन नौकरियों में न तो स्थायित्व होता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। काम की अनिश्चितता और कम आय के कारण ये लोग गरीबी की चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं। महिलाएँ अधिकतर घरेलू सहायिका का काम करती हैं, और उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है।

4. स्वच्छता और पेयजल संकट – अधिकतर बस्तियाँ जलापूर्ति व्यवस्था से नहीं जुड़ी होतीं। लोग सार्वजनिक नलों या टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। खुले में शौच की प्रवृत्ति अब भी कायम है, जिससे महिलाओं को विशेष असुविधा होती है। नालियों की सफाई नियमित नहीं होती, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बना रहता है।

5. महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव – महिलाएँ असुरक्षित, अशिक्षित और कमजोर आर्थिक स्थिति में होती हैं। यौन शोषण, घरेलू हिंसा और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएँ आम हैं। बच्चों को कुपोषण, बाल श्रम और शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

6. आपराधिक गतिविधियाँ और सामाजिक तनाव – बेरोजगारी और अभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में चोरी, नशा, जुआ जैसे अपराध पनपते हैं। नाबालिगों का अपराध की ओर आकर्षण भी चिंता का विषय है। पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास की कमी, और बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास, सामाजिक तनाव को जन्म देते हैं।

जोधपुर की मलिन बस्तियाँ केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक असमानता, प्रशासनिक उपेक्षा और जीवन की अनिश्चितता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। इनके प्रभावों को कम करने हेतु समावेशी योजनाएँ, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ, तथा समुदाय आधारित पुनर्विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

जोधपुर शहर में मलिन बस्तियों के लिए सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ

शहरीकरण के साथ–साथ जोधपुर सहित अधिकांश शहरों में मलिन बस्तियाँ अनेक सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं से निपटने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न नीतियाँ और योजनाएँ लागू की गई हैं। इनमें राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्लम सुधार प्रोग्राम एवं पुनर्वास योजनाएँ प्रमुख हैं। साथ ही, नगर निगम और नगर विकास प्राधिकरण की सक्रिय भागीदारी से शहर के मलिन बस्तियों के उन्नयन तथा पुनर्विकास में सुधार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

1. राजीव गांधी आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना – राजीव गांधी आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेषकर मलिन बस्तियों के निवासियों को किफायती और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना है।

राजीव गांधी आवास योजना – यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ती आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को न्यूनतम लागत पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में आवास निर्माण हेतु सब्सिडी, बैंक लोन में ब्याज में कमी एवं अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल होते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (च्ड।ल) – च्ड।ल का लक्ष्य 2022 तक किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना में शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को अपने घरों में परिवर्तित करने के लिए क्रेडिट, सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत लागू तकनीकी मानकों के अनुरूप घरों का निर्माण तथा मौजूदा झुग्गियों के नवीनीकरण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को सुरक्षित आवासीय संरचना प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार और जीविका के स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

2. नगर निगम नगर विकास प्राधिकरण की भूमिका – शहरी विकास में नगर निगम एवं नगर विकास प्राधिकरण का केंद्रीय योगदान महत्वपूर्ण है।

आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन – नगर निगम द्वारा आवासीय योजनाओं का कार्यान्वयन, लाइसेंस और निर्माण कार्यों की निगरानी की जाती है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास तथा सुधार के लिए सरकारी निधि का आवंटन एवं परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करना इनमें शामिल है।

नियमन एवं निगरानी – नगर निगम और नगर विकास प्राधिकरण अवैध कब्जा, अनियोजित बस्तियों और अव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। नियमित सर्वेक्षण एवं डेटा संग्रह के द्वारा बस्तियों की स्थिति, विकास और आवश्यक सुधारों की पहचान की जाती है।

सामुदायिक सहभागिता – उचित पुनर्वास तथा स्लम सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। नागरिकों की सुझावों, शिकायतों एवं असहमति को हल करने हेतु नगर निगम द्वारा संवाद मंच खोलने का प्रयास किया जाता है।

3. पुनर्वास योजनाएँ एवं स्लम सुधार प्रोग्राम – मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं सुधार के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य पहलें शामिल हैं –

पुनर्वास परियोजनाएँ – मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को नवीनीकृत आवास में स्थानांतरित करने के लिए, पुनर्वास योजना के अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता तथा आवास निर्माण में प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्वास कार्यक्रम का लक्ष्य न केवल घरों का निर्माण करना है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के भी इंतजाम करना है।

स्लम सुधार प्रोग्राम – स्लम सुधार प्रोग्राम में मौजूदा झुग्गियों के सुधार, बुनियादी संरचनाओं (जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क और बिजली की सुविधाएँ) में वृद्धि, और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पहुँच में सुधार करने पर जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम नयी तकनीकों, डिजिटल सर्वेक्षण और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करता है।

सामुदायिक विकास – पुनर्वास एवं स्लम सुधार प्रोग्राम के तहत स्थानीय समुदायों को स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं बाल शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ जोधपुर में मलिन बस्तियों के मुद्दे को दूर करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं। राजीव गांधी एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के माध्यम से किफायती आवास प्रदान करने का प्रयास करते हुए, नगर निगम की निगरानी, पुनर्वास एवं स्लम सुधार प्रोग्राम्स के द्वारा मौजूदा बस्तियों की स्थिति में सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है। इन पहलों से न केवल शहरी गरीबों को सुरक्षित और स्वच्छ आवास उपलब्ध हो रहे हैं, बल्कि शहर के समग्र विकास में भी सुधार की संभावनाएँ बढ़ रही हैं।

जोधपुर शहर में मलिन बस्तियाँ – चुनौतियाँ और समाधान के सुझाव

जोधपुर शहर, जो एक ऐतिहासिक और पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में तीव्र शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। इस तीव्र शहरी विकास के साथ–साथ मलिन बस्तियों की संख्या और उनका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। इन बस्तियों में

रहने वाले नागरिकों को अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि सरकार द्वारा कई सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी अनेक बाधाएँ इन प्रयासों को सफल होने से रोकती हैं।

1. वर्तमान सुधार प्रयासों में बाधाएँ –

क. प्रशासनिक जटिलताएँ – मलिन बस्तियों के उन्नयन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्सर विभागीय समन्वय की कमी देखी जाती है। नगर निगम, आवास बोर्ड, और शहरी विकास प्राधिकरण के बीच तालमेल का अभाव योजनाओं को धीमा करता है।

ख. भूमि स्वामित्व की समस्या – अधिकतर मलिन बस्तियाँ सरकारी या निजी भूमि पर अवैध रूप से बसी होती हैं। भूमि स्वामित्व स्पष्ट न होने के कारण पुनर्विकास या पुनर्वास योजनाएँ कानूनी अड़चनों में उलझ जाती हैं।

ग. वित्तीय संसाधनों की कमी – योजनाओं के लिए निर्धारित बजट अक्सर अपर्याप्त होता है। साथ ही, योजनाओं के लिए जारी धनराशि समय पर नहीं पहुँच पाती, जिससे निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं।

घ. सामाजिक अस्वीकार्यता – कभी–कभी पुनर्वास के अंतर्गत स्थानांतरण से प्रभावित परिवार नए स्थान पर जाने को तैयार नहीं होते। वे अपने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े रहना चाहते हैं, जिससे योजनाओं को लागू करने में मुश्किल होती है।

2. सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता

मलिन बस्तियों के विकास में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन– बस्तियों के भीतर से नेतृत्व विकसित कर योजनाओं में सहभागी बनाया जाए। इससे पारदर्शिता और स्वामित्व की भावना बढ़ती है।

जन–जागरूकता अभियान– योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाकर लोगों को योजना से जोड़ना आवश्यक है।

स्वयंसेवी संस्थाओं और छळव्े की भूमिका – ये संस्थाएँ सामुदायिक संगठन, महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक हो सकती हैं।

3. सतत शहरी विकास और नियोजन

क. दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता – मलिन बस्तियों की समस्या को केवल आवास निर्माण से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सतत विकास पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरणीय पहलुओं का समावेश हो।

ख. इंटीग्रेटेड स्लम डेवलपमेंट – शहर की समग्र योजना में मलिन बस्तियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्हें शहर के विकास से काटकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आवासीय योजना, सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

ग. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जुड़ाव – जोधपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मलिन बस्तियों को स्मार्ट सुविधाओं (जैसे डिजिटल सेवाएँ, स्वच्छता निगरानी, ळप्ै आधारित योजनाएँ) से जोड़ना चाहिए।

4. शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा

मलिन बस्तियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु शिक्षा और कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की सुलभता – बस्तियों के पास प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा के लिए बच्चों को पोषण, यूनिफॉर्म, पाठ्य सामग्री जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। ड्रॉपआउट रोकने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ।

ख. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास – युवाओं के लिए सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लंबिंग, बिजली कार्य जैसे तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएँ। महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर, सिलाई–कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

ग. स्वरोजगार योजनाएँ – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्वरोजगार योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को ऋण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। ैभ्ळ (स्वयं सहायता समूह) के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

घ. डिजिटल साक्षरता – आज के दौर में डिजिटल ज्ञान आवश्यक है। बस्तियों में डिजिटल केंद्र खोले जाएँ जहाँ लोग सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पा सकें।

जोधपुर शहर की मलिन बस्तियाँ एक गंभीर शहरी चुनौती हैं, जिनके समाधान हेतु केवल आवास निर्माण ही नहीं, बल्कि समग्र और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों में जब तक स्थानीय समुदाय की भागीदारी, शिक्षा और कौशल विकास जैसे आयाम नहीं जोड़े जाएँगे, तब तक सतत और न्यायपूर्ण विकास संभव नहीं हो सकेगा। नगर निगम, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र यदि मिलकर कार्य करें, तो जोधपुर को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष :– जोधपुर शहर, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है, पिछले कुछ दशकों में तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के दौर से गुजर रहा है। इस शहरी विस्तार ने जहाँ एक ओर शहर की भौतिक और आर्थिक सीमाओं को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी सामाजिक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। मलिन बस्तियों का विस्तार इन्हीं चुनौतियों में से एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है। मलिन बस्तियों के उद्‌भव के पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में होने वाला प्रवासन, सस्ती और सुलभ आवास की आवश्यकता, आर्थिक असमानता और सरकारी आवासीय योजनाओं की सीमित पहुँच। ये बस्तियाँ आमतौर पर शहर की बाहरी या उपेक्षित क्षेत्रों में बिना नियोजन के बसाई जाती हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

जोधपुर में सूरसागर, चोपासनी, जलोरी गेट जैसे क्षेत्रों में विकसित मलिन बस्तियाँ इस समस्या का जीवंत उदाहरण हैं, जहाँ हजारों परिवार अत्यंत असुविधाजनक स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इन बस्तियों में जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे न केवल निवासियों का जीवन स्तर प्रभावित होता है, बल्कि पूरे शहरी तंत्र पर दबाव बढ़ता है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु भूमि स्वामित्व, वित्तीय सीमाएँ और सामुदायिक सहभागिता की कमी जैसे कारण इन प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं दिला पा रहे हैं।

इसलिए, मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान केवल पुनर्वास या आवास निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित समग्र और सतत विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है। जब तक नीति निर्माण में मानवीय दृष्टिकोण नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक मलिन बस्तियों के मूलभूत कारणों को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. "जीम ैसनउ ंदक जीम बपजलरू न्तइंद च्वअमतजल ंदक जीम प्दवितउंस ैमबजवतष . श्रण्ड्ड श्रंपद
2. "ैसनउकवह डपससपवदंपतमरू । छवअमसष . टपोंूतनच
3. "डनउइंप ।अमदहमतेरू ैजवतपमे व िजीम बपजलश् ैसनउ क्ूमससमतेष . ठींतंजप
   च्तंकींद
4. "ैसनउेरू भ्वू जीमल ॅवताष दृ स्ॅतपहीज
5. "च्संदमज व िैसनउेष . डपाम क्ंअपे
6. "जीम न्तइंद च्ववतरू ।ै जनकल व िजीम ैसनउ क्ूमससमतेष . छण्ैण ठींतकूंर
7. "ैसनउ स्पमिरू ।ै जनकल व िन्तइंद च्वअमतजल पद प्दकपंष दृ त्ण्त्ण् ैींतउं
8. "प्देपकम जीम ैसनउेरू ैजवतपमे व ि नतअपअंस ंदक भ्वचमष . ।सवा डपीतं
9. "ैसनउ त्मींइपसपजंजपवद ंदक न्तइंद त्मदमूंसष दृ ।ण् ज्ञण् श्रंपद
10. ॅपापचमकपं
11. श्रवकीचनत क्मअमसवचउमदज ।नजीवतपजल – छंहंत छपहंउ श्रवकीचनत
12. डपदपेजतल व िीवनेपदह ंदक न्तइंद ।ििंपते त्रंेंजींद